उपर्युक्त अवधियों के दौरान राज्यों द्वारा सूचित फसलों के नुकसान का मुद्रा-मूल्य निम्नवत है :—

फसलों को नुकसान	(करोड़ रुपये)
पांचवीं योजना (1974 से 1977 की बाढ़ों के दौरान)	1998.52
छठी योजना	
(1) 1980	366.35
(2) 1981	497.96
(3) 1982	589.40
(4) 1983	1279.92

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का संस्थान, जोधपुर द्वारा 'खेजरी' के पेड़ और 'तूम्बा' फसल के सम्बन्ध में अनुसंधान

3123. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए गए मुख्य वृक्ष 'खेजरी' और 'वाणिज्यिक फसल 'तूम्बा' के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुसंधान के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त अनुसंधान के परिणाम किसानों तक पहुंचे, केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) 'खेजड़ी' के प्रवर्धन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसके प्रारम्भ से ही इस वृक्ष पर अनुसंधान कर रहा है। इस पर उपलब्ध जानकारी को एक मोनोग्राम के रूप में प्रलेखित किया गया है। एक जर्म-प्लाज्म बैंक के विकास के लिए यह संस्थान विशेषताओं में विस्तृत परिवर्तनशीलता सहित जल्दी बढ़ने वाले वृक्षों की पहचान करने हेतु अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कर रहा है। हाल ही में, वायु दाब-कलम के माध्यम से कायिक प्रवर्धन तकनीकों को मानकीकृत किया गया है। यह तकनीक बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए 'खेजड़ी' के सुधरे बीजों की आपूर्ति करके क्लोन-युक्त बीज बागानों की स्थापना करने में बहुत उपयोगी होगी।

तूम्बा की खेती पर किये गये अनुसंधान अन्वेषण से इसकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक कृषि विधि के विकास का पता चला है। बालू मिट्टियों में इसकी खेती करने की सस्य तकनीक को मानकीकृत किया गया है।

'खेजड़ी' (पत्तियों, फलियों और टहनियों) के विभिन्न हिस्सों के प्रवर्धन और लाभकारी उपयोग की जानकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा लोकप्रिय साहित्य के वितरण के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के सहयोग से इस फसल की खेती को बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र के किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए एक-एक हैक्टर के तूम्बा प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था की है।

उकई सिंचाई परियोजना

3124. श्री छोटूभाई गामित : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के अन्त तक गुजरात की उकई सिंचाई परियोजना पर कितनी धनराशि

खर्च की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उकाई सिंचाई परियोजना की बाईं और दाहिनी तरफ़ के तटबंधों का कुल कमान क्षेत्र कितना है और 1983 के अन्त तक इस क्षेत्र में से वर्षभर समुचित रूप से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही थी और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) सिंचाई के अन्तर्गत कम क्षेत्र लाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) दोनों नहरों की न्यूनतम और अधिकतम जल वहन क्षमता कितने क्यूसेक फिट है और इस समय उनमें कितना क्यूसेक फिट पानी बहता है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इन नहरों में निर्माण सम्बन्धी विभिन्न त्रुटियों के कारण उनकी सिंचाई क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता और क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) 1983-84 के अन्त अर्थात् मार्च, 1984 तक 134.93 करोड़ रुपए का व्यय होने की आशा है तथा ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

1982-83 तक किया गया व्यय	133.93
1983-84 के दौरान व्यय	1.00
1983-84 के अन्त तक योग	134.93 करोड़ रुपए

(ख) परिकल्पित सिंचाई क्षमता वाम तट नहर के अन्तर्गत 85,000 हैक्टेयर तथा दक्षिण तट नहर के अन्तर्गत 67,400 हैक्टेयर है। दोनों नहरों की कुल मिलाकर सिंचाई क्षमता 152400 हैक्टेयर है। राज्य सरकार ने 1984-85 के अपने वार्षिक योजना दस्तावेज में 1983-84 के अन्त तक वास्तविक सिंचाई उपयोगिता 38,000 हैक्टेयर होने का उल्लेख किया है। मौसमी सिंचाई तथा सम्पूर्ण वर्ष के दौरान होने वाली सिंचाई के क्षेत्र के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते।

(ग) राज्य सरकार ने जुलाई, 1984 में सूचित किया है कि कमानगत क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा उन्होंने परियोजना की सिंचाई क्षमता का पुन: मूल्यांकन किया है तथा अब दोनों नहरों से कुल मिलाकर क्षमता 1,27,000 हैक्टेयर होने का आयजा लगाया गया है। उन्होंने आगे यह सूचित किया है कि निम्नलिखित कारणों से परियोजना से उपयोगिता धीमी रही है :—

(1) परियोजना के कमानगत क्षेत्र का प्रमुख भाग ऊंचा-नीचा है तथा खेतों को सिंचाई योग्य बनाने से पहले भूमि के समतलन की आवश्यकता है।

(2) कमानगत क्षेत्र के अधिकांश कृषक जनजातियों के हैं तथा अपनी वर्तमान प्रणाली को छोड़कर सिंचित कृषि को अपनाने में उनको समय लगता है। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यरत होने तथा खेत नालियों के निर्माण, खेतों से जल निकास, वाराबन्दी और अन्य उपायों को शुरू करना जैसे उपायों के पैकेज से परियोजना से उपयोग के तेज हो जाने की आशा है।

(घ) वाम तट नहर की अभिकल्पित डिसचार्ज क्षमता 1236 क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड तथा दक्षिण तट नहर की 1272 क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड है। नहरों में पहुंचने वाले वास्तविक डिसचार्ज की मात्रा अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग होती है जो कि खेत में फसलों तथा वर्षापात की स्थितियों जैसे कई कारणों पर निर्भर करती है।

(ङ) राज्य सरकार ने नहरों में किसी ऐसे दोष की सूचना नहीं दी है जिससे कि उनकी सिंचाई क्षमता में कमी आए ।

Project for Cultivation of Sugarbeet in Coastal/Saline Areas

3125. SHRI AMAL DATTA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any proposal has been received for taking up project for cultivation of sugarbeet in coastal/saline areas ;

(b) if so, the steps Government have taken pursuant to such proposal ;

(c) the activity for promoting sugarbeet in Sunderban area, if any, taken by Government or sponsored by it ; the details of actual acreage, yield of beet and yield of sugar etc ;

(d) whether Government propose to take-up the promotion of sugarbeet in Sunderban ; and

(e) if so, the details of the proposal and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such activity has yet been taken up by the Government. However, Indian Council of Agricultural Research has sanctioned a research Scheme to Calcutta University to ascertain adaptability of this crop to saline conditions in general and Sunderban area in particular. Experiments are being conducted on 6 to 7 hectares in Sunderban area and average yield of 50 to 55 tonnes/ha has been obtained. About 6 tonnes/ha sugar yield has been estimated from sugarbeet.

(d) and (e). At present there is no such proposal under consideration of Government. However, Indian Council of Agricultural Research proposes to intensify research activities on sugarbeet cultivation in Sunderban areas for perfecting the production technology for this crop.

Financial Assistance to Orissa for Construction of Houses for Weaker Sections

3126. SHRI RASABEHARI BEHERA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government of Orissa have fully utilised the financial assistance provided by the Central Government for construction of houses for the people belonging to weaker sections, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, under the Centrally sponsored schemes during the last two years ; and

(b) if so, the details regarding the houses constructed during 1982-83 and 1983-84 alongwith the financial assistance provided for this purpose ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Housing, being a State subject, all the Social Housing Schemes including the houses for Economically Weaker Sections, are being implemented by the States/U.Ts. The Union Govt. provides Plan assistance in the form of block grants and block loans without being tied to any particular scheme. However, there is no Centrally Sponsored Scheme for houses for weaker sections SC/STs.

(b) Does not arise.

Decline in Price of Foodgrains due to Glut

3127. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total foodgrains production this year ;

(b) whether there is a glut of foodgrains